[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

मान्यवर, हमारी डिमांड है कि देश के सभी सरकारी अस्पतालों में रिक्त पड़े डॉक्टर्स और स्टाफ के पदों को तत्काल भरा जाए, साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाओं का प्रबंध किया जाए। निजी नर्सिंग होम्स में महंगे इलाज व चिकित्सा में धांधली की समीक्षाएं की जाएं। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाई जाए।

मान्यवर, हमारी एक डिमांड और भी है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक विधायक अपने एमपीलैड फंड से 25 लाख रुपये तक दे सकता है। हमसे भी लोग यही बात कहते हैं, इसलिए एमपीलैड फंड में भी अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनके इलाज के लिए कम से कम 50 लाख रुपये तक की व्यवस्था की जा सके, हर साल हम लोग भी गरीब लोगों के इलाज के लिए कुछ धन दे सकें, धन्यवाद।

श्री जावेद अली खान: सर, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

† **جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش) :** سر، میں مانّئے سدسئے کے ذریعے اٹھائے موضوع سے خود کو سمبدّھ کرتا ہوں۔

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डा. अमर पटनायक: सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to widen the scope of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 to include gender bias

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I rise to bring to the attention of the Government the urgent need to widen the scope of the Sexual Harassment of Women at Workplace (PoSH) Act to include gender bias.

Sir, sexual harassment has been dealt with in the country first by the Vishakha guidelines of the Supreme Court and then by the PoSH Act that Parliament passed in 2013. But that does not cover the range of other kinds of harassments that women are subjected to in the workplace. This can take many, many forms. It can take the form

†Transliteration in Urdu script.

of humiliation, it can take the form of exclusion from important tasks, it can take the form of removal of responsibilities and withholding of resources. There are numerous ways in which women are harassed at the workplace and their promotion is prevented. We have all heard of the glass ceiling. That is also an example of an impact of harassment of a particular kind.

Sir, how do we remedy this particular challenge that is faced by large numbers of women? One way to do is to ensure that there are redressal mechanisms within companies, but there is no standard method by which companies go ahead and address this challenge of harassment of women. And, because of inconsistencies, there is a problem for women to be able to get proper justice.

Sir, this can get much, much worse. In many multinational corporations, the cases are heard and passed on to foreign committees and there is no response within the country to the challenges faced by women. There are often the other problems; there are false accusations, there are whisper campaigns, subtle rumours passed on to other companies saying this is a troublesome person and do not hire her. These are all ways in which women face tremendous difficulties. How do we pay attention to this and turn it around? This is even more important because the Economic Survey is pointing out that the female labour force participation has already dropped from 33 per cent in 2011-12 to 25.3 per cent in 2017-18. So, this could be one of the causes for that as well. What I would suggest to the Ministry of Women and Child Development is to include a new provision on prevention of gender bias harassment and discrimination in the PoSH Act. That is one specific thing that can be done and possibly it can be done under the rules itself. Also, to widen the jurisdiction of internal complaints committee and to ensure that there is an NGO member and, at least, half the members are women there; that in multi-nationals, they include members from the Indian branch of the company; also that there is a time-barred resolution of this issue, to publish the number of complaints of gender bias in their annual reports and to improve awareness of the Act. Sir, there is a constitutional provision for right to work with human dignity under Articles 14, 15, etc.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Those who are associating, send the names. This is an important issue.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P. WILSON: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करती हूँ।

श्री रेवती रमन सिंह: महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Shri Chunibhai Kanjibhai Gohel, not present. Now, Dr. Ashok Bajpai.

Commercialization of education

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे गम्भीर विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, आज शिक्षा का व्यवसायीकरण बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, जिनका एकमात्र उद्देश्य है- शिक्षा के माध्यम से अधिक से अधिक धन अर्जित करना-- मान्यवर, हमारा वह देश है, जहाँ कृष्ण और सुदामा एक साथ संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं होती थी। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा से जो 'विद्या ददाति विनयं', विद्या विनय देती थी, शिक्षा से सेवा-भाव आता था, राष्ट्र-भावना आती थी, राष्ट्र के प्रति चिन्तन मन में होता था, लेकिन आज जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, मान्यवर, एक-एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक-एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दो-दो करोड़, तीन-तीन करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। मान्यवर, जो छात्र एम.डी., एम.एस. करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तीन करोड़ देकर आयेगा, उसका स्वभाव एकदम कॉमर्शियल होगा, जनता के प्रति न सेवा-भाव होगा, न राष्ट्र-भावना होगी। इस तरह से शिक्षा का क्षरण हो रहा है।

मान्यवर, यही हाल उच्च शिक्षा का हो रहा है। आज देश के तमाम विश्वविद्यालयों में self financed courses के नाम पर नये-नये कोर्सेज़ संचालित हो रहे हैं और उन self financed courses के लिए बड़ी लम्बी फीस ली जाती है, जो एक सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के लिए सम्भव नहीं है। इस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण निजी क्षेत्र में तो हो ही रहा था, सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में भी self financed courses के नाम पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है।

मान्यवर, यह बड़ी चिन्ता की बात है। जो स्नातक होता था, शिक्षा से उसके मन में समाज सेवा की भावना की भावना होती थी, लोक सेवा की भावना होती थी और वह समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करता था और यही शिक्षा का मूल उद्देश्य था। लेकिन शिक्षा इतनी महँगी और व्यावसायिक हो जाने के कारण शिक्षा से निकल कर जो भी स्नातक आते हैं, उनके मन में होता है कि जो हमने व्यय किया है, उससे अधिक हमें अर्जित करना है और इसको लेकर वह शुरू से ही, प्रारम्भ से ही, वे उससे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, व्यवसाय के रूप में ही उसका उपयोग करने का काम करते हैं। मान्यवर, यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है कि हमारा देश, जहाँ शिक्षा सर्वोपरि होती थी, हम दुनिया की अगुआई किया करते थे, वहाँ आज शिक्षा का जो क्षरण हो रहा है, उसके कारण हमारी मानव संवेदनाएँ कम हो रही हैं, समाज के प्रति जो हमारे सरोकार हैं, वे घट रहे हैं, राष्ट्र-प्रेम की भावना कम हो रही है। ये सारे चिन्ता के विषय हैं- शिक्षा की गिरावट से और शिक्षा के व्यवसायीकरण से।